

संपादकीय

से घिरती दुनिया

कुलभूषण उपमन्यु

इरान-इजराइल युद्ध को लेकर पूरी दुनिया एक बार फिर संकटों से घिरती नजर आ रही है। इरान ने इजराइल पर अपने डोन और

से धरता नजर आ रहा हा। ईरान न इजराइल पर अपने द्वान आर मिसाइलों से प्रतीक्षित पहला प्रत्यक्ष हमला कर दिया है। इजराइल सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी के अनुसार 'ईरान ने 300 से अधिक आत्मघाती ड्रोन, बैलेस्टिक मिसाइलों तथा क्रूज मिसाइलों द्वारा हमला कर दिया है। वास्तव में यह संकटपूर्ण स्थिति है।' इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अबीव में युद्ध की घातक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और कहा, 'हमारी रक्षात्मक प्रणाली जहां तैयार, तैनाव और तत्पर है वहीं अब हम रक्षात्मक तथा आक्रमणात्मक, दोनों तरह से किसी भी स्थिति के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं।' वास्तव में यह तनाव और तनातनी उस समय चरम पर जा पहुंची जब इजराइल के 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमले से ईरान के एक वरिष्ठ जनरल सहित सेना के सात अधिकारी मारे गए। उसी दिन इजराइल को दंडित करने की घोषणा, ईरान द्वारा सार्वजनिक रूप से कर दी गई थी। अखिरकार, आशंका हकीकत में बदल गई और ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से बौछार शुरू कर दी और कहा कि इजराइल ने हमले की जो पहल की थी, उसी का यह जवाब है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के आधार पर यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र हमला होता है, तो वर्तमान चार्टर में कुछ भी व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अन्तर्निहित अधिकार को खराब नहीं करेगा, जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय नहीं करती। ईरान ने इसका ध्यान रखते हुए 13 दिन बाद अखिरकार, इजराइल की कार्रवाई का बदला लिया। इस बहुउद्देशीय हमले का प्रमुख लक्ष्य इजराइल के एअर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करना रहा। ईरान ने इस हमले को 'ऑपरेशन दू प्रॉमिस' नाम दिया और कहा कि यह इजराइल के अपराधों की सजा है। इस घटना से सर्वक इजराइल ने अपने आयरन ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किए जो अधिकांश हमलों को नाकाम करने में सफल रहे। ईरानी मिसाइलों ने नेगेव रेगिस्ट्रेशन में इजराइली एयरबेस को भी तबाह कर दिया। तेहरान की खबर के अनुसार यहीं से इजराइल ने दमिश्क में हमला करके ईरानी दूतावास पर मिसाइलें दागी थीं।

विचार

स्वार्थ की जंग में राष्ट्रीयता की शहादत

डा. रवान्द्र अरजारया

देश में चुनावी जंग जारी है। सभी राजनैतिक पार्टियां अपनी

निधारत नातया-रातया के अलावा ताल्कालक हथकंड आजमन में लगाए हैं। बंगल का चुनावी इतिहास आतंक के साथ में हमेशा से ही फलता-फूलता रहा है। कभी लाल सलाम का रंग चढ़ता रहा तो कभी दीदी की दादागिरी चलती रही। घुसपैठियों की दम पर सत्ता हथियाने की मुहिम चलाने वाली तृणमूल मुखिया पर तो देश की सरकारी एजेन्सियों तक पर आक्रमण करवाने के आरोप लगते रहे हैं। पूर्व घोषित दंगों का व्यवहारिक स्वरूप सामने आने के बाद से तो वहाँ के आम निवासियों में भय व्याप होने लगा है। पुलिस के सामने ही अपराधों का कीर्तिमान गढ़ने का जो सिलसिला प्रारम्भ हुआ, वह निरंतर जारी है। तुषीकरण के हथियार से देश को रक्रुजित करने का षड्यंत्र करने वाली पार्टीयां कभी देश के टुकडे-टुकडे गैंग को चुनावी जंग में जहरीली सोच के साथ उतारती हैं तो कभी आतंक के पर्याय रहने वालों को गले लगाते हैं। सिध्दान्तों की होली जलाकर स्वार्थ सिद्धि का परिणाम पाने वालों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी होती जा रही है। हिन्दूवादी छवि के साथ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था। उनके शरीर त्यागते ही पार्टी हथियाने का संग्राम शुरू हो गया। विरोधी नीतियों के पक्षधरों के साथ मिलकर सत्ता-सिंहासन लेने का क्रम चल निकला। मुसलमानों को संरक्षण देने के नाम पर बनाई गई आल इण्डिया मजलिस-ए-इंतेहादुल मुस्लिमीन ने अनेक अवसरों पर विरोधियों को गले लगाकर अपने सिध्दान्तों को कफन पहना दिया। दलितों की मसीहा बनने वाली बहुजन समाज पार्टी की नीतियों ने आधारभूत सिध्दान्तों को तिलांजलि देकर अपने विरोधियों के साथ मिलकर अनेक बार समर्पण कर्म। उससे बहुत साथ दोनों दो आपने अपनी दो पार्टी लना यह 2024 के लाक्सभा चुनाव का सबसे अलग बना रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विपक्षी दलों को नोटिस भेजना भले एक रूटीन काम हो सकता है मगर इसकी टाइमिंग विपक्ष को सत्तारूढ़ दल पर हमला करने का मौका जरूर दे रही है। वैसे देखा जाए तो पहले भी सत्तासीन पार्टियों द्वारा ऐसी संस्थाओं वें उपयोग की कहानी न्यायालयों द्वारा भी दुरुपयोग के विशेषण से नवाज़ी गई है परन्तु अबकी यह मामलत प्रभाव क्षेत्र के हिसाब से बहुत आगे निकल गया है इनकम टैक्स का नोटिस सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट लेकर आया है। शनिवार को ज़री किये गए डिमांड नोटिस के बाद कांग्रेस पर आयकर विभाग का कुल लगभग 3,567 करोड़ रूपये बकाया बैठता है। ताजा डिमांड नोटिस 1745 करोड़ रूपये का है जो बित वर्ष 2014- 2015, 2015- 2016 और 2016- 2017 का है। हालांकि इसकी आशंका कांग्रेस शुक्रवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर चुकी थी कि उसे अभी और परेशान किया जाएगा। इसके पहले जो कांग्रेस को नोटिस मिला था वह 1823 करोड़ रूपये का था। यह बकाया पांच अलग-अलग वित्तीय वर्षों के लिए था और इसमें मूल और ब्याज दोनों राशियां शामिल हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस नोटिस में वित्तीय वर्ष 1994-1995 में

सरकार बनाइ। जनता दल यूनाइटड न ता अपन आदशा का स्वाय की देहलीज पर किस्तों में कल्प करके अनेक बार सत्ता पर काबिज हुई। स्वार्थपूर्ति में बाधा पड़े ही असंतुष्टों व्यारा तो पुराने संगठन से दूरी बनाकर स्वयं के दल की घोषणा तक की जाती रही है। शासक बनने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार लोगों ने देश की अतीतकालीन संवेदनाओं, भावनाओं और चिन्तन को अनन्त गहराई में दफन कर दिया है। इस सारे क्रिया कलाओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों, न्याय पत्रों, संकल्प पत्रों आदि में परिलक्षित हो रहा है। अनेक दलों के संयुक्त गठबंधनों की अपनी कोई साझी कार्ययोजना सामने नहीं आई है। गठबंधनों के सभी दल अपनी अगल-अलग सोच को लेकर सत्ता में पहचने के बाद व्यवहार में लाने वाली कार्ययोजना का ढांचा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधनों का स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई पड़ रहा है। मुटु भर सीटों पर चुनाव लड़ने वाले दल भी राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण करने में जुटे हैं। कहीं साम्प्रदायिक खाई को चौड़ा करने की होड़ लगी है तो कहीं जातिगत जनगणना के आधार पर शक्ति संघर्ष का आधार तैयार किया जा रहा है। कहीं अलग-अलग विशेषाधिकारों की बकालत हो रही है कहीं स्वतंत्रता के विकृत मायने परोसे जा रहे हैं। स्वार्थ की जंग में राष्ट्रीयता की शहादत लेने वालों को देश का सम्मान, विकास और सौहार्द की करत्ति चिन्ता नहीं है। वे नेत्रवान होने के बाद भी धृतराष्ट्र बनने पर तुले हैं, मीरजाफर बनकर सुख बटोरना चाहते हैं और करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर स्वार्थपूर्ति। ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी तो क्या राष्ट्र का नागरिक तक कहना, शर्म की बात है। जिस देश के नागरिक अपनी धरती से उगने वाले अन्न और बहने वाले पानी पर जीवन यापन करने के बाद भी उसके टुकड़े-टुकड़े करने का मंसूबा पाल रहे हों वहां पर शान्ति, सुख और समृद्धि की बयार कभी भी जीवनदायिनी वायु नहीं बन सकती। अतीत में कोलकता के रास्ते से गोरों ने विनाश का दूत बनकर प्रवेश किया तो वहीं से सुभाषचन्द्र बोस जैसे स्वाधीनता संग्राम के पुरोधा ने भी स्वाधीनता का शंखनाद किया था। मगर गोरों की चालों ने राष्ट्रान्यक सुधार को गुमनामी के अंधेरे में ढकेलकर अपने चमचों को देश का महान नेता बना दिया था। आजाद हिन्द फौज के रणबांकुरों से भयभीत होकर देश छोड़ने पर मजबूर हुए गोरों ने जाते-जाते मजहब के नाम पर देश को टुकड़ों में विभाजित कर दिया था किन्तु आज अनेक राजनैतिक दल हमारे भारत के पुनः टुकड़े करने पर तुले हैं। विभाजनकारी, विध्वंशकारी और विनाशकारी सोच को संरक्षण देने वालों को मुंह तोड़ जबाब दिये बिना राष्ट्र को विकास के रास्ते पर ले जाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। ऐसे में व्यक्तिगत हितों को त्यागकर राष्ट्र हित के आधार पर ही मतदान करना आवश्यक नहीं बल्कि नितांत आवश्यक है, तभी देश बच सकेगा।

ग्रामीण अ

डा. जयंतीलाल मंडारी

यह अभूतपूर्व खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था नए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुआयामी उपयोगिता देते हुए दिखाई देगी। हम उम्मीद करें कि लोकसभा चुनाव के बाद गठित होने वाली नई सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ कृषि सुधारों की डार एवं तेजी से आगे बढ़ेगी हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के तेजी से बढ़ते हुए सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ने से निजी खपत में भी तेजी आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और प्रमुख मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि अनुकूल मानसूनी मौसम के कारण इस वर्ष 2024 में भारत में अच्छी वर्षा के स्पष्ट संकेत खेती और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा कहा गया है कि इस वर्ष 2024 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद है जिससे कृषि गतिविधियों में और तेजी आएगी। ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी। गौरतलब है कि विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। गांवों में न केवल कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक विक्री हो रही है, वरन् गांवों में फ्रिज, दोपहिया वाहन और टीवी के खरीदारी में सबसे उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य के प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में विद्युत एक दशक में शहरी परिवारों के मुकाबले ग्रामीण परिवारों का खर्च तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय, ग्रामीणों के रोजगार की मनरेगा योजना

पृथ्वी दिवस का बढ़ता महत्व.....



के प्रति जागरूकता फैले और हमारे रहन-सहन, उत्पादन पद्धतियां और कायदे कानून पर्यावरण मित्र विकास की दिशा में मुड़ें। सन् 2000 से पृथ्वी दिवस को जलवायु परिवर्तन की दिशा में लक्षित किया गया है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान में पर्यावरण की मुख्य समस्या बनती जा रही है। इसकी ओर ध्यान देना जरूरी हो गया है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय वस्तु 'पृथ्वी ग्रह बनाम प्लास्टिक' रखा गया है। प्लास्टिक मिट्टी, पानी और वायु का प्रदूषक बनता जा रहा है। जमीन पर पड़े हुए प्लास्टिक से धूप के कारण अपर्दन से टूट कर सूक्ष्म कण मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करने का काम करते हैं। पानी में मिल कर मछलियों के शरीर में पहुंच कर खाद्य श्रृंखला का भाग बन कर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाते हैं। जलाए जाने पर वायु में अनेक विषैली गैसें वायुमंडल में छाड़ते हैं जिससे वैश्विक तापमान बढ़ के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। प्लास्टिक दैनिक जीवन का ऐसा भाग बन गया है कि इससे बचना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, पुनर्चक्रीकरण, और जो बच जाए उसको उत्तम धुआं

रहित प्रज्वलन तकनीक से ताप विद्युत बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि इससे भी थोड़ा गैस उत्सर्जन तो होता है, किन्तु जिस तरह शहरी कचरा डंपिंग स्थलों में लगातार लगाने वाली आग और गांव में खुले में जलाया जा रहा प्लास्टिक धुआं फैलता जा रहा है, उससे तो यह हजार गुणा बेहतर है। स्वीडन ने तो यूरोप के अनेक देशों से सूखा कचरा आयात करके उससे बिजली बनाने का व्यवसाय ही बना लिया है। उसके पास जो तकनीक है उसमें केवल दशमलव दो (.2) प्रतिशत ही गैस उत्सर्जन होता है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पैकिंग सामग्री तैयार करना नवाचार की दृसरी चुनौती है। गांव में भी अब तो प्लास्टिक कचरे के अंबार लगाते जा रहे हैं। आधुनिक दैनिक प्रयोग की तमाम वस्तुएं प्लास्टिक में ही पैक होकर आ रही हैं। प्लास्टिक के पुनःचक्रीकरण के लिए यह जरूरी है कि प्लास्टिक और अन्य सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाए और कबाढ़ी को दिया जाए। जो बच जाए उसे निबटाने के दूसरे सुरक्षित तकनीकी उपायों की सरकारें व्यवस्था करें। एक विचार यह भी जोर पकड़ रहा है कि जो पैदा करे, वही कचरे के प्रबंधन का जिम्मेदार ठहराया जाए, ताकि ये पैकिंग

करके सामान बेचने वाली कंपनियां पैकिंग सामग्री एकत्रित करवा कर वापस लें और रीसाइक्लिंग की व्यवस्था करें। किन्तु केवल प्लास्टिक ही जलवायु परिवर्तन का कारक नहीं है। रासायनिक कृषि के कारण भी भूमि की जैविक पदार्थ धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे कार्बन पदार्थ का भूमि में संचय नहीं होता। दूसरा भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करके और वैज्ञानिक आधार पर विकसित करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। भारत में इस दिशा में कुछ काम होना शुरू भी हुआ है, किन्तु इसे अभी तक मुख्य धारा बनाने में सफलता नहीं मिली है, जिसके लिए अधिक वैज्ञानिक शोध की जरूरत है ताकि रासायनिक विधि के बगाबर ही उत्पादन करके दिखाया जाए और अन्न सुरक्षा की चुनौती पर कोई खतरा आने की चिंता न रहे। जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की है। हमारे देश में कुल विद्युत उत्पादन 428 गीगावाट है, जिसमें से 71 फीसदी कोयले और जीवाशम इंधन से हो रहा है। सच्च ऊर्जा उत्पादन 168.96 गीगावाट है, जिसमें से 42 गीगावाट जल विद्युत का उत्पादन है। किन्तु जल विद्युत भी जब बड़े बांधों के माध्यम से बनाई जाती है तो जलाशयों में बाढ़ से सर्वचित जैव पदार्थ आक्सीजन रहित सड़न द्वारा मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से छह गुणा ज्यादा वैश्विक तापमान वृद्धि का कारक है। इसलिए एक सीमा से ज्यादा जल विद्युत का प्रसार भी ठीक नहीं। सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही है। भारतवर्ष में पिछले कुछ सालों में सौर ऊर्जा उत्पादन में अच्छा काम हुआ है। भारतवर्ष में 2030 तक 500 गीगावाट सच्च ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आशा है इसे हम प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु बड़े ऊर्जा पार्क बना कर स्थानीय संसाधनों पर कुछ जगहों पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है, जिससे कई समुदायों की रोज़ी-रोटी के संसाधन छिन जाते हैं। इसके विरुद्ध कई आवाजें उठती रहती हैं।

लोकसभा चुनाव...चोरी फिर भी सीनाजोरी

कांग्रेस पाटा द्वारा वित्तीय दंड भी शामिल है। आयकर विभाग के ये नोटिस कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि पार्टी ने 2023- 2024 के आयकर रिटर्न में पार्टी की कुल संपत्ति ही 1430 करोड़ रुपये बतायी थी। इसमें 657 करोड़ रुपये का फंड, 340 करोड़ की चल अचल संपत्ति और लगभग 388 करोड़ का लिकिड कैश बताया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पार्टी अपनी कुल संपत्ति बेचकर भी आयकर विभाग का फाइन नहीं भर सकती। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी दिवालिया घोषित हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय राजनीति की एक ऐसा घटना होगी जो अगर सकारात्मक प्रभाव को लेकर आगे बढ़ी तो कभी भी कोई पोलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के नियमों को सुविधानुसार उपयोग में लाने की भूल से बचेगी। लेकिन अगर इसी को नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा तो बदले की भावना से ग्रसित होकर स्वयं सत्ता में आने पर पूर्वकालिक सत्तारूढ़ पार्टियों के ऊपर भी ऐसी ही कार्यवाही करेगी। राहुल गांधी प्रेस कॉफेंस में इस बात की धमकी दे चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस और समस्त इंडिया गठबंधन आयकर विभाग के नोटिस को जिस तरह से गलत बता रहा है वो नोटिस सही हैं या गलत शनिवार को जारी 1745 करोड़ रुपये के नोटिस के अलावा दूसरा मामला 1700 करोड़ के नोटिस का है। मामला 2017 से 2021

क बाच कांग्रेस का कश के रूप में मिल चढ़ आए अन्य कैश अनियमितताओं से जुड़ा है। इसमें लगभग 526 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसका स्पष्ट हिसाब-किताब कांग्रेस के पास नहीं है। दरअसल 2019 में आयकर विभाग के कई छापें के दौरान यह बात खुल कर सामने आई थी कि दो कंपनियां मेधा इंजीनियरिंग और कमलनाथ के करीबी की एक कम्पनी ने कैश में कांग्रेस को ये पैसे दिए हैं। आयकर विभाग को इन कंपनियों द्वारा कांग्रेस को ट्रांजेक्शन की रसीद मिली है। सूत्रों के अनुसार 20 करोड़ के एक पेंट का ब्यौरा आयकर विभाग के पास ऐसा भी है जिसमें कमलनाथ के जरिये पैसा सीधे कांग्रेस ऑफिस को गया है। आयकर विभाग दावा कर रहा है कि ये सारे पैसे रिश्वत के हैं जिसे मध्य प्रदेश में मंत्रियों और अफसरों को दिया गया था और जो धूम फिर कर कांग्रेस पार्टी को फंड के रूप में मिला है। यह आयकर कानून के सेक्षण 13() का उल्लंघन है जिसके अनुसार 2,000 रुपये से ज्यादा कैश पेंट कोई पार्टी नहीं ले सकती। इसी तरह तीसरा मामला 135 करोड़ का है। यह 2018- 2019 के बीच का है। इस दौरान कांग्रेस ने साढ़े 14 लाख रुपये का दान नकद में लिया और टैक्स रिटर्न भी 33 दिन की देरी से फाइल किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उस वित्त वर्ष में कांग्रेस की कुल आय को ही टैक्स रिबेट के दायरे से बाहर कर दिया गया जो 135 करोड़ था। राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट आयकर कानून की धारा 13(1) के तहत क्लेम करनी

पड़ता है। कांग्रेस पर इसा प्राविधिक कानून का उल्लंघन का आरोप है। चौंक पार्टी ने इस वित्त वर्ष के दौरान 33 दिन की देरी से टैक्स रिटर्न फाइल किया तो आयकर विभाग ने कांग्रेस की कुल 199 करोड़ की आय पर टैक्स के छूट के दावे को खारिज कर दिया। हालांकि 2021 में विभाग ने 105 करोड़ की अनियमितता के एवज में नियमानुसार 20 फीसदी यानी 21 करोड़ चुकाने को कहा था जिसके बाद केस की सुनवाई तक स्टे लग जाता। पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप 16 मार्च को आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये की वसूली कर ली। इसमें से 103 करोड़ के करीब का जुर्माना था और बाकी के 21 करोड़ इस जुर्माने पर लगे ब्याज की रकम थी। अमाउंट लियन है अर्थात् बैंक अकॉउंट में फाइन वाली अमाउंट पर रोक लगा दी गई है, बाकी पैसों को पार्टी खर्च कर सकती है। यहां कांग्रेस छूट का भ्रम फैला रही है कि उसके बैंक अकॉउंट फ्रीज कर दिये गये हैं। मगर वास्तव में ऐसा है नहीं। अब इनके अकॉउंट में सिर्फ फाइन जितने पैसे थे तो क्या ही किया जा सकता है और अब तो कुल फाइन जितने पैसे भी कांग्रेस के एकाउंट में नहीं बचे हैं। चौथा मामला 1994-95 की आय और उससे जुड़े हिसाब-किताब की गड़बड़ी से है। इस केस में आयकर विभाग ने पार्टी पर 53 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यहां भी आयकर कानून की धारा 13 के सेक्षन ए के उल्लंघन की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अलावा तृणमूल कांग्रेस को भी आयकर विभाग का नोटिस मिला है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बढ़ने का परिदृश्य

डा. जयंतीलाल भंडारी

यह अभूतपूर्व खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था नए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुआयामी उपयोगिता देते हुए दिखाई देगी। हम उम्मीद करें कि लोकसभा चुनाव के बाद गठित होने वाली नई सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी हाल ही में एशियातीन विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के तेजी से बढ़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ने से निजी उपकरण में भी तेजी आ रही है। भारतीय

बढ़ने से निजा खपत में भी तजा आ रहा है। भारतवासी मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और प्रमुख मौसम एजेंसी स्कार्फेट ने कहा है कि अनुकूल मानसूनी मौसम के कारण इस वर्ष 2024 में भारत में अच्छी वर्षा के स्पष्ट संकेत खेती और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा कहा गया है कि इस वर्ष 2024 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सामान्य रहेंगे की उम्मीद है कि जिससे कृषि गतिविधियों में और तेजी आएंगी। ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी। गौरतलब है कि विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। गांवों में न केवल कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, वरन् गांवों में फिल्म, दोपहिया वाहन और टीवी की खरीददारी में सबसे उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य के प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पिछले एक दशक में शहरी परिवारों के मुकाबले ग्रामीण परिवारों का खर्च तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय, ग्रामीणों के रोजगार की मनरेगा योजना



तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रय शक्ति और मांग में भारी इजाफ हुआ है। इससे ग्रामीण भारत की आर्थिक ताकत में इजाफ हुआ है। यद्यपि अभी आम चुनाव के बाद जून 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के पूर्वरूप लेने में कोई दो माह बकाया है, लेकिन उच्च प्रशासनिक स्तर पर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मकसद से जिन क्षेत्रों के लिए आगामी पांच सालों के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाना शुरू की गई है, उनमें कृषि भी प्रमुख है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस समय पूरी दुनिया में भारत को खाद्यान्न का नया वैश्विक कटोरा माना जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। गेहूं तथा फलों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर तथा सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर भारत केला, आम, अमरुल, पपीता, अदरक, भिंडी, चावल, चाय, गन्ना, काजू, नारियल, इलायची और काली मिर्च आदि के प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना

जाता है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के मामले में भारत देशी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में कृषि एवं ग्रामीण विकास का नया आधार तैयार हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 15 पीसदी है। सरकार के द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए एक के बाद एक रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। कृषि बजट में 10 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। किसानों के सशक्तिकरण, फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा 11 करोड़ से अधिक किसानों के जनधन खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 3 लाख करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित होने जैसे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, कृषि, रसायन, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण, जैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तुओं के अधिक उपयोग से किसानों को लाभ हुआ है और इन सभसे जहां एक ओर भारत में कृषि क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी एवं लाभदायक बन रहा है, वहाँ दूसरी ओर छोटे किसान अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। जहां कोविड-19 की आपदाओं से लेकर अब तक भारत

वैश्विक स्तर पर दुनिया के जरूरतमंद देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है, वर्हीं भारत ने दुनियाभर में कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का अवसर भी मुहियों में लिया है। भारत से कृषि निर्यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत से अनाज, गैर-बासमती चावल, बाजरा, मक्का और अन्य मोटे अनाज के अलावा फलों एवं सब्जियों के निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई है। भारत के कृषि उत्पादों के बड़े बाजारों में अमरीका, चीन, बांगलादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया शामिल हैं। कई छोटे देशों के बाजार भी मुहियों में आए हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व बाजार में भारत के मसालों की खुशबू की धमक बहुत अधिक बढ़ी है। चूंकि देश में मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, अतएव इसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग बढ़ाने के रूप में रेखांकित हो रहा है। इस समय दुनिया में कृषि निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। भारत से करीब करीब 50 हजार डॉलर से अधिक मूल्य का कृषि निर्यात होता है। खाद्य प्रसंस्करण में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। इस समय भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 लाख टन से बढ़कर दो सौ लाख टन हो गई है। पिछले नौ वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण निर्यातों में 15 गुना वृद्धि हुई है। निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के तहत पांच क्षेत्र हैं। एक डेयरी क्षेत्र, दो फसल एवं सब्जी प्रसंस्करण, तीन अनाज का प्रसंस्करण, चार मांस मछली एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण तथा पांच, उपभोक्ता वस्तुएं पैकेट बंद खाद्य और पेय पदार्थ। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के यह भी उल्लेखनीय हैं कि इन प्रमुख पांचों क्षेत्रों की व्यापक संभावनाओं को मुहियों में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे ग्रामीण भारत लाभान्वित हो रहा है।

मां कामाख्या धर्मादा दृस्त द्वारा स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक



भिलाई (विश्व परिवार)। मां कामाख्या धर्मादा दृस्त भारतवर्ष के द्वारा दक्षिण मुख्य हनुमान मन्दिर हुड़को (भिलाई) में स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया। मन्दिर की सफाई की गई और आसपास के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य कराना चाहिए, जैसे हम सब कार्य करते हैं वैसे आसपास के क्षेत्र को साफ सुधार रखने से हम बीमार नहीं पड़ें।

दृस्त के द्वारा इस कार्य में भिलाई प्रभारी रूपेंद्र गुप्ता, मातुशक्ति प्रभारी अंशु गुप्ता, हेमत गुप्ता, प्रतिमा गुप्ता, सहित दृस्त के समस्त

गणिनी गुरु मां स्वरित भूषण माताजी के कर कमलो से संलेखनारत शांति देवी बाकलीवाल की हुई दीक्षा



छुलिका 105 श्री उपशममति माता जी के नाम से जानी जाएगी

कोटा (विश्व परिवार)। स्वरित शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है और बहुत ही सार्थकता सिद्ध करता है स्वरित का अर्थ होता है मंगलकारी। और ऐसा ही कोटा की धरा पर हो रहा है।

भारत गौवं स्वरितधाम प्रणेत्री परम् तिरुपती लेखनी गणिनी अर्थिका 105 श्री स्वरितभूषण माताजी के कर कमलो से दीक्षा संपन्न हुई।

यह पावन पुनीत दीक्षा श्री 1008 मुनिसुव्रताथ दिग्बावर जैन त्रिकाल चौबीसी मन्दिर आर.के पुरम में हुई। निश्चित रूप से पूज्य गुरु मां जब कई चर्चाएं पूर्व जब कोटा आई थी तब भी कीर्तिमान तिवारी गया और नया इतिहास बना जो युगों युगों तक जीवंत रहेगा। निश्चित रूप से आज का यह क्षण अविस्मरणीय कहा जाएगा।

एक विवरण- कोटा नगर की श्रीमती शांतिदेवी बाकलीवाल विगत कई दिनों से जो

-अधिकेक जैन लुहुड़िया

आर्यिकारन आदिमति माताजी का सांतवा समाधि दिवस मनाया, शतिनाथ मण्डल विधान की पूजा अर्चना कर अनुष्ठान किया



नयापारा राजिम (विश्व परिवार)। नगर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के अवसर पर विभिन्न संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विधानाचार्य सुरेश शास्त्री एवं अशोक भाणी के मंत्रोच्चारा द्वारा शान्तिनाथ मण्डल विधान कीर्तिमान तिवारी गया। विधान से पूर्व-प्रद्वालुओं को भगवान शान्तिनाथ का अधिष्ठक एवं शान्तिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान गंजेबाजे के साथ शान्तिनाथ मण्डल विधान का शुभारंभ किया गया।

जैन समाज के प्रवक्ता विमल जौला एवं राकेश संघी ने बताया कि विधान के सोधर्म इन्द्र द्वारा मण्डप पर पूर्व मंगल करतों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है। इस दौरान विधान में विनाय

जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र की असली पहचान : डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर

स्पर्श संस्था द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत लोकतंत्र में एक-एक वोट के महत्व से नागरिकों को अवगत कराया

रायपुर (विश्व परिवार)। लोकसभा सामान्य निवाचन 2024 में प्रदेश में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए नुक़ड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्पर्श सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान रायपुर द्वारा विभिन्न बसितियों गुड़ियारी, सतोंपी नगर, कुशालपुर एवं चांगोरापाल के बसितियों में प्रचार प्रसार किया गया। इस अवसर पर स्पर्श सामाजिक संस्थान रायपुर के अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर ने कहा कि यह

एक सुनहरा अवसर है इस दौरान विधान में घोटे

तौर पर कला जैता के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस अवसर पर मतदाताओं को लोकसभा निवाचन 2024 के मतदाता जागरूकता के माध्यम में जनकारी दी एवं लोकतंत्र के महापर्व में सभी नागरिकों को शामिल होने का आहारन किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में नागरिकों को लोकतंत्र में निवासियों को मतदाता के लिए व्यापक



देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने, मतदाताओं को भय मुक एवं बिना किसी प्रोतोभ के अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। नागरिकों को मतदान के महत्व के संबंध में समाजान्वय यथा लोकतंत्र में संसद की भूमिका के संबंध में विस्तार से जनकारी दी गई है। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को लोकतंत्र में जनकारी दी गई है। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को शामिल होने का आहारन किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संवेदित करते हुए डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर ने नागरिकों को

बताया कि लोकतंत्र में मजबूती का आधार सिर्फ मतदान होता है। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को शपथ दिलाया गया। सभी नागरिकों से मतदान के केंद्रों में जाकर अपने मताधिकार और करताओं का पालन करने की अपील की गई। जागरूक मतदाता ही असली पहचान मेरा वोट मेरी परचम शत् मतदाता जागरूकता के लिए विधान सभा के अधिकारी को निवासियों को मतदाता के महत्व से अवगत कराया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

पथरे प्रमुख श्रीजीओं को मंच से शाल, दुपट्टा एवं पगड़ी पहनकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया गया।

शोध यात्रा में अलग-अलग मंदिरों से मंडलों से

